Retired Govt. employees are charged at the rate applicable to the private persons for the stay in the Touring Officers Guest Houses. For Holiday Homes, they are charged at par with the Central Govt. employees, subject to the conditions that no advance booking will be done.

गैर-सरकारी खनन क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी लागू करना

*316. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान-उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी इकाइयों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) प्रबंधन में कर्मचारियोंकी सहभागिता संबंधी योजना, जो इस समय विद्यमान है, दिसम्बर, 1983 में तैयार और अधिसूचित की गई थी। यह योजना विशेष रूप से छूट प्राप्त उद्यमों के अलावा, सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू है। इसमें कार्यशाला (शॉप) और संयंत्र (प्लांट) स्तरों पर द्विपक्षीय मंच के गठन की संकल्पना है। उपयुक्त समझे गये उद्यमों में, इसे बोर्ड स्तर पर भी लागू किया जाना था। इस योजना में उत्पादन, गुणवत्ता, लक्ष्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याण उपाय, पर्यावरणीय मुद्दों, गैरहाजिरी उद्यमों के वित्तीय निष्पादन आदि से संबंधित कतिपय कार्यसम्बद्ध मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श की व्यवस्था है।

राज्य सरकारों से प्रबन्धन में कर्मचारियों की सहभागिता योजना, 1983 अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लागू करने का अनुरोध किया गया था। खनन उद्योग सहित निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी इस योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता योजना, 1983 एक स्वैच्छिक योजना है अतः इकाईयों द्वारा इसे लागू किये जाने की बाध्यता नहीं है।

Objectives of NBCFDC and National SCs/STs Finance and Development Corporation

*317. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the objectives behind formation of National Backward Classes Finance and Development Corporation and National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation;

(b) what was their paid-up capital at the time of formation and as on date;

(c) sector-wise allocation and achievement made during Eighth Plan and Ninth Plan in the States/Union Territories;

(d) the reasons for poor performance in the North-Eastern Region and the steps taken to improve; and

(e) the nodal agency appointed and particulars of programmes initiated in Assam by each during the last five years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) The main objective of the National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance & Development Corporation (NSFDC) is to provide financial assistance at concessional rates to members of SCs/STs and Other Backward Classes below double the poverty line for self-employment through income generating schemes. The two Corporations provide loan through State Channelising Agencies (SCAs).

(b) The paid up capital of the two Corporations at the time of formation